

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2954**  
**जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**गोदावरी नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार**

**2954. श्री राजभाऊ पराग प्रकाश वाजे:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का नासिक शहर में और इसके आस-पास गोदावरी नदी के प्रदूषण उपशमन, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम चल रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यक्रमों के विभिन्न खण्डों की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट और ठोस योजना है कि नासिक शहर में और उसके आस-पास गोदावरी नदी 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के विशाल आयोजन से पहले प्रदूषण मुक्त हो जाए; और
- (घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए बजटीय प्रावधानों और आबंटनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क) से (घ): यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज और औद्योगिक बहिःस्त्रावों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार गंगा नदी के अलावा अन्य नदी घाटियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

राज्य सरकार के अनुसार, नासिक के छह सीवेज जोनों में 365 एमएलडी सीवेज उत्पादन के लिए 392.5 एमएलडी क्षमता के 11 एसटीपी स्थापित किए गए हैं।

एनआरसीपी के तहत, गोदावरी नदी के संरक्षण के लिए नासिक में 100 एमएलडी क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए गए हैं। अमृत 1.0 के अंतर्गत गंगापुर में 18 एमएलडी और पिंपलगांव खंब में 32 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता तैयार की गई है।

त्रिंबक नगर परिषद के अनुसार, गोदावरी नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए, वर्तमान में 1.9 एमएलडी एसटीपी बनाया गया है। अस्थायी आबादी में वृद्धि और आगामी कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना में राज्य सरकार द्वारा 34.00 करोड़ रुपये की लागत से 4.5 एमएलडी एसटीपी उपचार क्षमता को मंजूरी दी गई है।

\*\*\*\*\*